BSNL EMPLOYEES UNION
Recognised Union in BSNL
(Registered Under Indian Trade Union Act 1926. Regn.No.4896)
CHQ:Dada Ghosh Bhawan, Opp. Shadipur Bus Depot., New Delhi – 110008
Email: bsnleuchq@gmail.com, website: bsnleu.in

P. Abhimanyu
General Secretary

Phone: (O) 011-25705385
Fax : 011- 25894862

बीएसएनएलईयू / 102 (सर्कुलर नंबर 6) 21 जून, 2020

सेवा में,

सर्किल सचिव,
केंद्रीय पदाधिकारी,
और जिला सचिव।

15–06–2020 को हुई केंद्रीय सचिवमंडल की बैठक के निर्णय।

प्रिय साथियों,

बीएसएनएलईयू के केंद्रीय सचिवमंडल (जो केंद्रीय पदाधिकारियों से बना है) की बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15.06.2020 को किया गया। कॉम. अनिमेश मित्रा, अध्यक्ष, ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी 25 केंद्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। शुरुआत में, सभी प्रतिभागी एक मिनट के लिए मौन खड़े रहे और वडोदरा सीईसी बैठक के बाद निधन होने वाले साथियों, और साथ ही प्रवासी श्रमिकों, जिन्होंने लॉक–डाउन लागू होने के बाद अपने गृह राज्यों के रास्ते में अपना जीवन खो दिया, उनको श्रद्धांजलि दी। कॉम. पी अभिमन्यु महासचिव द्वारा चर्चा के लिए एक नोट प्रस्तुत किया गया। सभी केंद्रीय सचिवमंडल सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। गहन विचार–विमर्श के बाद, केंद्रीय सचिवमंडल बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए: –

(1) बैठक में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि, मेहनतकश वर्ग का मेहनत से जीता हुआ अधिकार, यानी दिन में 8 घंटे काम करने का अधिकार छीन लिया जा रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर दिन के काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। यह नोट करना चिंताजनक है कि कई राज्यों में, सभी श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया गया है और इस तरह से काम करने वाले लोगों पर गुलामी लादी जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए डेढ़ वर्ष के लिए फ्रीज किय गया हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की उदासीनता के कारण 10 करोड़ से अधिक प्रवासी श्रमिक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान कामकाजी लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने सरकार से अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए सभी गैर–आयकर परिवारों के लिए 7,500/– रुपये प्रति माह हस्तांतरित करने की मांग की है। लेकिन, सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र पर भी एक क्रूर हमला किया है। एक ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। दूसरी ओर, उनकी सरकार निजीकरण करने और भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, रक्षा कारखानों, कोयला खानों, बैंक, बीमा, पोर्ट और डॉक्स इत्यादि को इन क्षेत्रों में 100 प्रतिषत एफडीआई की अनुमति देकर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने के लिए सभी कदम उठा रही है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें (सीटीयजू), बीएमएस को छोड़कर, श्रम कानूनों में बदलाव, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर एकजुट रूप से प्रतिरोध आंदोलनों का निर्माण कर रहे हैं। सीटीयूज ने 3 जुलाई, 2020 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का आह्वान किया है। वे लंबे समय तक असहयोग और अवज्ञा जैसे संघर्षों के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन की योजना बना रहे हैं। केंद्रीय सचिवमंडल की बैठक ने निर्णय लिया कि, बीएसएनएलईयू को सीटीयूज की सभी कॉलों को लागू करना चाहिए।

(2) बैठक ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन में हुई देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, जिसमें बीएसएनएल की 4 जी सेवा की शुरूआत, बांड जारी करने के लिए संप्रभु गारंटी, संपत्ति विमुद्रीकरण आदि शामिल है। 8 महीने हो चुके हैं जब सरकार ने बहुत धूमधाम और दिखावे के साथ रिवाइवल पैकेज की घोषणा की थी। लेकिन, वीआरएस के तहत 79,000 कर्मचारियों की छटनी करने के अलावा, सरकार ने बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत, बीएसएनएल के 4 जी उपकरण की खरीद को रोकने की साजिश रची गई है। वाणिज्य मंत्रालय ने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (टीईसीसी) द्वारा उठाई गई कुछ अतर्कसंगत आपत्तियों के आधार पर, बीएसएनएल द्वारा 4 जी उपकरणों की खरीद के लिए मंगाई गई निविदा को रोक दिया है। यह स्पष्ट है कि बीएसएनएल को 4 जी सेवा शुरू करने से रोकने के लिए निहित स्वार्थ काम कर रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उन निहित स्वार्थों के लिए भी इसमें मदद कर रही है।

जहां तक नॉन–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निपटारे का संबंध है, बैठक इस बात से पूरी तरह निराश है कि, बीएसएनएल प्रबंधन एक लापरवाही और अस्थिरता का रवैया अपना रहा है। इसलिए, बैठक ने पूरे देश में 26.06.2020 को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, एक दिन के धरने का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें बीएसएनएल के पुनरुद्धार पैकेज को तत्काल लागू करने की मांग की गई, जिसमें 4 जी सेवा की शुरूआत और बीएसएनएल कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं का शीघ्र समाधान भी शामिल है।

(3) बैठक में लॉक–डाउन के कारण लगाए गए सभी प्रतिबंधों के बावजूद जीवंत कामकाज को बनाए रखने के लिए सीएचक्यू की सराहना की गई। बैठक ने संतोष व्यक्त किया कि, 'अनुबंध श्रमिक राहत कोष' बनाने के रास्ते सीएचक्यू ने ठेका श्रमिकों को राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। 20 सर्किलों में कुल 65 लाख रुपये एकत्र किए गए हैं और ठेका श्रमिकों को खाद्य सामग्री वितरित करके राहत प्रदान की गई है। बैठक ने दिन में 12 घंटे काम करने और कुछ अन्य मुद्दों पर विरोध करते हुए सामाजिक दूरी रखते हुए 21.05.2020 को लंच आवर में प्रदर्शन के आयोजन के लिए सीएचक्यू की सराहना की।

(4) बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय सचिवमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए सीएचक्यू की सराहना की गई। बैठक ने सीएचक्यू से केंद्रीय कार्यकारी समिति, बीएसएनएल वर्किंग वीमेन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों के साथ–साथ अखिल भारतीय केंद्र की बैठकों के आयोजन के लिए डिजिटल मंच का उपयोग करने का आह्वान किया। कोविड–19 संकट के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, बैठक ने सर्किल, जिला और शाखा यूनियनों को जमीनी स्तर के कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार बनाए रखने का आह्वान किया। बैठक ने सर्किल, जिला और शाखा यूनियनों से अनुरोध किया कि वे सीएचक्यू के वेबसाइट पर अपलोड किए गए सभी संदेशों और सर्कुलरों और व्हाट्सएप संदेषें को जमीनी स्तर के कर्मचारियों को तुरंत, जहाँ भी आवश्यक हो, क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके, भेजने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

(5) कॉम. के जी बोस का जन्मशताब्दी, 7 जुलाई, 2020 को है। केंद्रीय सचिवमंडल ने फैसला किया कि कॉम. के जी बोस का जन्म शताब्दी वर्ष कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए, पूरे एक वर्ष के लिए मनाया जाना चाहिए। बैठक ने निर्णय लिया कि, कॉम. के जी बोस की फोटो पर 7 जुलाई, 2020 को सभी सर्किल और जिला यूनियन कार्यालयों में माला पहनाई जानी चाहिए। यह भी तय किया गया है कि कॉम .के.जी.बोस के दूरदर्शी विचारों पर कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार, विशेष बैठकें आदि आयोजित की जानी चाहिएं।

(6) यूनियन पत्रिकाएं, **टेली क्रूसेडर** और **बीएसएनएल स्वर** लॉक–डाउन के कारण अप्रैल, 2020 के महीने से मुद्रित नहीं हो रही हैं। बैठक ने स्थिति की समीक्षा की और फैसला किया कि जुलाई महीने के अंक को ऑनलाइन मुद्रित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, स्थिति की समीक्षा की जाएगी और पत्रिकाओं के मुद्रण के संबंध में अखिल भारतीय केंद्र द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

(7) बैठक ने निर्णय लिया कि बीएसएनएल में होने वाले भारी बदलाव के मद्देनजर सीएचक्यू द्वारा एक नई पदोन्नति नीति की मांग की जानी चाहिए। नई पदोन्नति नीति तैयार करने के लिए सीएचक्यू को सुझाव देने के लिए केंद्रीय सचिवमंडल द्वारा एक दो सदस्यीय समिति, जिसमें कॉम. स्वपन चक्रवर्ती, डिप्टी जीएस और कॉम. चेल्लप्पा, एजीएस, शामिल हैं, नियुक्त गई है। केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक में चर्चा के बाद नई पदोन्नति नीति के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इसके अलावा, यह केंद्रीय सचिवमंडल के ध्यान में लाया गया था कि, बीएसएनएल के कार्यों की आउटसोर्सिंग में बड़े पैमाने पर धन का रिसाव हो रहा है। इस संबंध में इनपुट एकत्र करने के लिए, जिसके आधार पर सीएचक्यू प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाएगा, बैठक में एक दो सदस्यीय समिति नियुक्त की गई, जिसमें कॉम. जॉन वर्गीज, एजीएस और कॉम. पी. आर. परमेस्वरन, संगठन सचिव शामिल हैं।

(8) टेलीकॉम फैक्टरियों के पुनर्गठन के संबंध में, बैठक ने यह मांग करने का निर्णय लिया कि, एक अलग 'टेलीकॉम फैक्ट्रीज सर्किल' बनाया जाए और सभी दूरसंचार कारखानों को इस दायरे में लाया जाए।

(9) अखिल भारतीय केंद्र ने लॉक–डाउन अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स को रु. 25,000 /– का दान किया है। केंद्रीय सचिवमंडल ने इस दान को मंजूरी दे दी।

बैठक में सभी सर्किल यूनियनों से यह सत्यापित करने का अनुरोध किया गया कि मई, 2019 से शुरू होने वाली यूनियन सब्सक्रिप्शन के पूरे सीएचक्यू कोटे का भुगतान सीएचक्यू को किया गया है या नहीं। बैठक ने एक बार फिर दोहराया कि, किसी भी सर्किल यूनियन को सीएचक्यू कोटा प्राप्त नहीं करना चाहिए और सर्किल प्रशासन को एनईएफटी के माध्यम से कोटा को सीधे सीएचक्यू को भेजने के लिए बाध्य करना चाहिए।

सभी सर्किल और जिला यूनियनों से अनुरोध है कि वे केंद्रीय सचिवमंडल के फैसलों को पूरी तरह से लागू करें।

सधन्यवाद
आपका,

(पी अभिमन्यु)
महासचिव